

## असम में बाढ़ का कहर बरकरार पीएम मोदी ने सांसदों संग की समीक्षा

**नई दिल्ली/गुवाहाटी (एजेंसी)।** असम में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को असम के सांसदों के साथ बैठक कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। वहीं, राज्य के अधिकारी विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपने एक माह का वेतन दान करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने असम के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर सांसदों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहत एवं बचाव कार्यों में असम सरकार के साथ मिलकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कुशलक्षेम की कामना करते हुए कहा कि केंद्र हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर, शिवसार्ग जिले के नौजान क्षेत्र सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी रज्जयशी क्षेत्रों में घुस गया है। सैकड़ों घर तलाशनी हो गए हैं और सड़क संपर्क बाधित होने से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित परिवारों के सामने भीख, खच्चड़ पेयजल और आश्रय की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव अभियान तेज कर



दिना गया है। बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए यूपजोर पल को छोड़कर राज्य के सभी विधायकों ने बाढ़ राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए अपने एक माह का वेतन दान करने का निर्णय लिया है। विधानसभा अध्यक्ष राजजीत कुमार दास ने घोषणा की कि वह स्वयं और उपाध्यक्ष हब्ले टेरोन अपना एक माह का वेतन राहत कोष में देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा सचिवालय के सभी कर्मचारी भी पीड़ितों को सहायता के लिए अपने एक दिन का वेतन दान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारीका ने इस पल्ल का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक भी एक माह का वेतन बाढ़ राहत कोष में देंगे। वहीं, राज्य में तृणमूल कांग्रेस के एकमात्र विधायक शेरमन अली अहमद ने भी अपने एक माह का वेतन दान करने की घोषणा की है। बाढ़ प्रभावित असम और नागालैंड में भारतीय वायुसेना का मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान लगातार जारी है। खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों के बावजूद वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्गम और जलमग्न क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित वायुसेना के अनुसार, पिछले दस दिनों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से 458 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

# पेपर लीक संशोधन विधेयक पर लोकसभा में तीखी बहस

**प्रियंका गांधी बोलीं- 'पीएम कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलें', सुप्रिया सुले ने शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल**

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** लोकसभा में मालवार् को सार्वजनिक परीक्षा (अनुविद्य) साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पक्ष चर्चा के दौरान सप्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्षी संसदों ने सरकार पर परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने में विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि सप्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। कई बार हंगामा की स्थिति बनी, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने सदस्यों से चर्चा को केवल विधेयक तक सीमित रखने की अपील की।

**सुप्रिया सुले ने कहा- यह राजनीति नहीं, छात्रों के भविष्य का सवाल**

एनसीपी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक बहस का विषय नहीं, बल्कि देश के करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में जनता के विश्वास से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024



में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन उसके प्रभावी क्रियान्वयन में कमी रही, जिसके कारण सरकार को अब संशोधन लाना पड़ रहा है। उन्होंने हाल के छत्र आंदोलनों का उल्लेख करते हुए कहा कि छात्रों और अभिभावकों में गहरा असंतोष है। सुले ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली, परीक्षा प्रणाली और कोचिंग संस्थाओं के बढ़ते प्रभाव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष



जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही छात्रों का भरोसा बहाल कर सकती है। सुप्रिया सुले ने सुझाव दिया कि सरकार सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाए तथा संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन कर व्यापक चर्चा के बाद ऐसी व्यवस्था तैयार करे, जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार का विरोधी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोगी है।

## प्रियंका गांधी का सरकार पर तीखा हमला

चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस कानून को वर्ष 2024 में बड़े दावों के साथ लागू किया गया था, उसके बावजूद अब तक पेपर लोक के किसी बड़े आरोपी को सजा नहीं मिल सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की पहचान सार्वजनिक की जा रही है, लेकिन कथित तौर पर पेपर लोक के जिम्मेदार लोगों के नाम सामने नहीं लाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को केवल नहीं समितियाँ बनाने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को वास्तविक सुधार करना चाहिए। उन्होंने राधाकृष्णन समिति की संरचना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनका शिक्षा क्षेत्र से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केवल अलग-अलग कैमरा एंगल से वीडियो बनाकर नतीजा पीढ़ी को प्रभावित नहीं किया जा सकता, बल्कि जरूरत है कि 'कैमरे का नहीं, दिल

का एंगल बदला जाए।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई ने सरकार को छवि को नुकसान पहुँचाया है और सरकार को युवाओं की आवाज सुननी चाहिए। प्रियंका गांधी ने हाल के छात्र आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि वह धायल छात्रों से मिलने राम मनोहर लोहिया अस्पताल गई थीं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर पैसंदेज गन के इस्तेमाल को लेकर भी जवाब मांगा और कहा कि देश के छात्र, अभिभावक और शिक्षक इस मामले में पारदर्शिता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनौती है सरकार जनता की सेवक होती है और युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने पूरा शिक्षा मंत्री को लेख एक विवादित टिप्पणी की, जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। संसदीय कार्य मंत्री किरें रिजजू ने कहा कि बिना प्रामाण्य के किसी भी प्रकार के चरित्र पर टिप्पणी करना उचित नहीं है और ऐसे बयान को सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए।

## संक्षिप्त ख़बरें

## जापान में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल ढही

**टोक्यो।** दक्षिणी जापान में मॉलबार को आए 7.1 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई। भूकंप के तेज झटकों से कुमामोटो प्रांत और आसपास के इलाकों से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, आग लगान की घटनाएं सामने आईं और रेल सेवाएं प्रभावित हो गईं। एक शांतिपूर्ण अर्थ की दूसरी मॉलल दहने से 50 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। शहत एवं बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर अभियान चला रहे हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार शाम 4:27 बजे आया। इसका केंद्र कुमामोटो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में और जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। भूकंप के तेज झटके पूरे क्यूशू द्वीप सहित आसपास के कई क्षेत्रों में महसूस किए गए, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कुमामोटो प्रांत के काशिमा शहर स्थित एक शांतिपूर्ण मॉल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा। भूकंप के दौरान मॉल की दूसरी मंजिल का एक हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे वहां मौजूद कई लोग मलबे में फंस गए।

## जौहर यूनिवर्सिटी ध्वस्तीकरण मामला: अब तीन अगस्त को होगी सुनवाई

**रामपुर।** रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अब तीन अगस्त को मंडलायुक्त एच रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीओ) के अध्यक्ष की अदालत में सुनवाई होगी। इससे पहले न्यायालय ने आली सुनवाई तक विश्वविद्यालय परिसर के खिलाफ किसी भी प्रकार की ध्वस्तिकरण कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा रखी है। गौरतलब है कि रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीओ) के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई को आदेश जारी करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में निहित 38 भवनों को बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाया गया बताते हुए उनके ध्वस्तिकरण के निर्देश दिए थे। प्रशासन का कहना है कि संबंधित भवन विकास प्राधिकरण की स्वीकृत के बिना निर्मित किए गए हैं, इसलिए नियमानुसार कार्रवाई की गई। प्रशासन के इस आदेश को जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन और उसके ट्रस्ट की ओर से मंडलायुक्त एवं आरडीओ अध्यक्ष आंजय कुमार सिंह को अदालत में चुनौती दी गई है। याचिका में ध्वस्तिकरण आदेश को निरस्त करने और विश्वविद्यालय के पक्ष को विरत से सुने जाने की मांग की गई है।

## अंतिम रिपोर्ट का मसौदा अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी सरकार



समक्ष पेश की जाएगी। सॉलिसिटर् जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए सुझावों के अनुसार चार सिमुलेशन परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि ईडेशनरस ऑफ इंडियन पायलट्स के पास कोई भी तकनीकी जानकारी या सुझाव है तो वह हमें ऐआईवी को उपलब्ध कराया जा सकता है। जांच एजेंसी आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रारण कर उचित कार्रवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट एक गैर-सरकारी संगठन, एक विधि छत्र तथा हार्दसे में जान गंवाने वाले पायलट के पिता द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इन याचिकाओं में न केवल दुर्घटना की स्वतंत्र और न्यायालयी निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 13 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान एएआईबी की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि 12 जून, 2025 को हुए विमान हादसे से संबंधित कॉम्पिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) और फ्लाइट डेटा व वीडियो रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। एजेंसी ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच से जुड़े नियमों के तहत इस तरह की सामग्री को किसी बाहरी संस्थित या आम जनता के साथ साझा करने पर पूर्ण

वैधानिक प्रतिबंध हैं। ऐसा करना विमान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं की जांच) नियम, 2025 का उल्लंघन माना जाएगा।

गैरतलब है कि एअर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट एआई-171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई थी। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

विमान का संचालन केप्टन सुमीत सभरवाल और सह-पायलट केप्टन क्लाव्ड कुंदर कर रहे थे। इस भीषण हादसे में कई लोगों की जान गई थी, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपणी भी शामिल थे। अब इस बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही सुनवाई और एएआईबी की आंतिम रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

**कांवड़ यात्रा: 60 हजार कांस्टेबल, 5,500 दरोगा तैनात**

**लखनऊ (एजेन्सी)।** आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन को तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेशभर में सुसज्ज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 60 हजार से अधिक कांस्टेबल और करीब 5,500 उपरीक्षक (दोरांगे) तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) भी पूरी यात्रा के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखेगा। इस संधर्भ में जानकारों ने दहे हुए अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) बीरू भास्कर ने बताया कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को

सुरक्षा के साथ-साथ आम नागरिकों को होने वाली असुविधा को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस उद्देश्य से विस्तृत यातायात एवड़ाजरी जारी की गई है, ताकि यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि यात्रा में ड्यूटी पर तैनात किए जा रहे सभी पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए संवेदशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, खुफिया तंत्र तथा एटीएस की निगरानी भी रहेगी। अधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था को समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

## छह इनामी समेत 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

**रांची (जुंसेी)**। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार को प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन से जुड़े 16 नक्सलियों में रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने वालों में छह इनामी नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल 39 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इस समूह में पांच महिला नक्सली भी शामिल हैं। पुलिस ने इहे राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान की बड़ी उपलब्धि बताया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में संगठन का एक रीजनल कमेटी सदस्य, एक जोनल कमेटी सदस्य, दो सब-जोनल कमेटी सदस्य और दो एरिया कमेटी सदस्य शामिल हैं। लंबे समय से सक्रिय इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण से संगठन की



उसकी भूमिका सामने आई थी। पुलिस ने बताया कि वह एक मार्च को मनोहरपुर, छोटानगर और झारियाकेला थाना क्षेत्रों की सीमा से लगे जंगल में हुए आईईडी विस्फोट की भी आरोपी है। इस विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया था। सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थीं। आत्मसमर्पण करने वालों में जौनल कोबरी सदस्य चंदन लोहरा भी शामिल है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 78 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उस पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चंदन लोहरा लंबे समय से संगठन की गतिविधियों पर प्रमुख संभावक रहा है। उसके मुख्याधार में लौटने से नक्सली संगठन की सक्रियता

पर प्रभाव पड़ेगा। आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार और गोला-बारूद भी जमा कराया। बरामद हथियारों में दो एके-47 राइफल, छह ईसाई राइफल, 38 मैगजीन और 1,562 ईसाई कारतूस शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कई नक्सली वारदातों में किया गया हो सकता है, जिसकी जांच की जाएगी। झारखंड पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों से पूछताछ की जा रही है ताकि संयुक्त की गतिविधियों, हथियारों के नेटवर्क और सक्रिय सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा सके। पूछताछ के बाद उन्हें राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत आवश्यक सहायता, प्रशिक्षण और पुनर्वास की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा, जिससे वे सामान्य जीवन जी सकें।

## सेवाओं को भी रखा जाए अलर्ट मोड पर

बचाव कार्यों और जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से आवश्यक सार्वजनिक संसाधन अपनयन करवाए जाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके। सुनिश्चित की जा रहे कि मुख्यमंत्री धामी ने निदेश दिए कि राज्य में संचालित हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा जाए। यदि किसी दुर्घटना या आपदा प्रभावित क्षेत्र में रहत सामग्री पहुंचाने अथवा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने पहुंचाने की आवश्यकता पड़े तो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा

कि रहत एवं बचाव कार्यों में समय पर प्रतिक्रिया देना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने चारदाम यात्रा को देखते हुए यात्रियों की सुस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में भारी बारिश, भूस्खलन या सड़क बाधित होने की आशंका हो, वहाँ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकना ज़रूरी। मौसम और मार्ग की स्थिति सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे यात्रा की अनुमति दी जाए। साथ ही यात्रियों को समय-समय पर मौसम और मार्ग की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।

## स्वाति मालीवाल का केजरीवाल पर हमला, पंजाब के पेपर लीक मामलों पर उठाए सवाल

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** राज्यसभा सांसद स्वाति भालीवाल ने मंगलवार को पंजाब में अद्वितीय पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच (आप) और उसके राष्ट्र-संयोजक पार्टी के केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में पंजाब में छह बड़े पेपर लीक हुए, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर आम जनता को नहीं बताया। उन्होंने केजरीवाल ने चुप्पी साध रही है। और मलिक ने दावा किया कि पंजाब में विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान कई बार प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं और नकल को घटाना सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में 19 जुलाई को आयोजित फार्मसी परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर नकल हुई, जिससे परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं।



उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक केवल परीक्षा व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास और भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उनके अनुसार, यदि समय रहते भ्रमवीर कारवाइ नहीं की गई तो प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शिता और निष्पक्षता पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा। स्वाति मालीवाल ने कांकेरिज जनता पार्टी (सीजेपी) को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सीजेपी, आम आदमी पार्टी की 'बी टीम' के रूप में काम कर रही है। मालीवाल ने आरोप लगाया कि इस संगठन का गठन आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों ने किया और इसके पीछे आर्थिक सहयोग भी वहीं से मिला।



# खाद्य प्रसंस्करण में बढ़ा निवेश युवा-महिला उद्यमियों का बढ़ा रुझान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में निवेश की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। प्रदेश सरकार की उन्नत प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत 15.08 करोड़ रुपये के आठ नए निवेश प्रस्तावों को अप्रैजल समिति ने राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बढ़ता निवेश प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने, कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार और निवेशकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं और निवेश



प्रस्तावों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा अब पारंपरिक व्यवसायों से आगे बढ़कर आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना में रुचि दिखा रहे हैं। इसके साथ ही महिला उद्यमी भी इस क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं, जो प्रदेश में उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक संकेत है। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बी.एल. मोणा की अध्यक्षता में सोमवार को गोमतीनगर स्थित

रेशम निदेशालय में अप्रैजल समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आठ नए निवेश प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। तकनीकी और वित्तीय परीक्षण के बाद सभी प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों के साथ राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की गई। इन परियोजनाओं में नमकीन, बेड एवं रस्क, सोया आधारित उत्पाद, पास्ता, पोल्टी फीड तथा अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा ऑन-ग्रिड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना से संबंधित परियोजनाओं पर भी विचार किया गया। अपर मुख्य सचिव बी.एल. मोणा ने निवेशकों से कहा कि वे स्थानीय किसानों से अधिक से अधिक कच्चे माल की खरीद

सुनिश्चित करें, जिससे कृषि और उद्योग के बीच मजबूत समन्वय स्थापित हो सके। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, अग्नि सुरक्षा और अन्य वैधानिक स्वीकृतियों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं में भी नीति के अनुरूप सभी तकनीकी और दस्तावेजी मानकों को पूरा किया जाना आवश्यक है। संबंधित निवेशकों को बैंक अप्रैजल, आयकर और जीएसटी रिटर्न सहित सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार का मानना है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण राज्यों में शामिल करना है, जहां कृषि उत्पादों का अधिकतम मूल्य संवर्धन हो सके।

# भाजपा प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा का जन्मदिवस वाल्मीकि समाज ने धूमधाम से मनाया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 27 जुलाई 2026 भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा का जन्मदिवस रविवार को वाल्मीकि समाज द्वारा भव्य रूप से मनाया गया। यह कार्यक्रम परिवर्तन चौक, लखनऊ स्थित रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आयोजित किया गया, जहां समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अभिजात मिश्रा को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने अभिजात मिश्रा के सामाजिक एवं सांठनात्मक कार्यों की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ, सफल एवं दीर्घायु जीवन की मंगलकामनाएं व्यक्त कीं। समारोह में वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया तथा समाज के प्रति उनके योगदान की प्रशंसा की। इस अवसर पर अमन वाल्मीकि, राहुल वाल्मीकि, संतोष वाल्मीकि, अशोक वाल्मीकि, शिवराज



कुमार, राजन वाल्मीकि, आलोक वाल्मीकि, शनि वाल्मीकि, सिद्धार्थ, अनूप बाजपेई, पवन वाल्मीकि, रश्मि वाल्मीकि, सुजीता वाल्मीकि, अनिता सहित वाल्मीकि समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित

रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितजनों ने अभिजात मिश्रा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं निरंतर जनसेवा के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

# बकाया मजदूरी मांगने पर दित्यांग मजदूर की पिटाई, जान से मारने की धमकी

.....पहले मजदूरी मांगने पर मारपीट, अगले दिन रास्ता रोककर दोबारा हमला; मुयमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत, पुलिस जांच में जुटी ।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

निगोहां, लखनऊ। निगोहां थाना क्षेत्र में बकाया मजदूरी मांगना एक दित्यांग मजदूर को भारी पड़ गया। आरोप है कि ठेकेदारी का काम करने वाले तीन लोगों ने पहले मजदूरी मांगने पर उसके साथ मारपीट की और अगले ही दिन रास्ता रोककर दोबारा हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उसे जान से मारने और दूसरा पैर भी तोड़कर पूरी तरह दित्यांग बना देने की धमकी दी। मामले में पीड़ित ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। लालता खेड़ा निवासी ललित उर्फ बाबू पुत्र अयोध्या प्रसाद ने बताया कि वह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है। वह गांव के ही विनोद कुमार, संतोष कुमार और रंजीत के साथ ठेकेदारी में मकान निर्माण कार्य कर

रहा था। उसकी कुछ मजदूरी लंबे समय से बकाया थी। पीड़ित के अनुसार, सोमवार शाम करीब छह बजे उसने संतोष कुमार से अपनी बकाया मजदूरी मांगी। इस पर तीनों आरोपी भड़क गए और गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी। किसी तरह जान बचाकर वह वहां से निकला और निगोहां थाने में शिकायत दी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ललित का आरोप है कि मंगलवार को खेत जाते समय तीनों आरोपियों ने उसका रास्ता रोक लिया, धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और लात-थुंसों से बेरहमी से पीटा। पीड़ित का कहना है कि वह पहले से ही एक पैर से

“**क्या बोले थाना प्रभारी निगोहां थाना प्रभारी रविंद्र कुमार कनौजिया ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।**”

दित्यांग है, इसके बावजूद आरोपियों ने उसकी दित्यांगता का मजाक उड़ाते हुए धमकी दी कि दूसरा पैर भी तोड़ देंगे और पूरी तरह विकलांग बना देंगे। घटना से सहमे पीड़ित ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग की है। उसका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उसके साथ कोई भी गंभीर घटना हो सकती है।

## ग्रामीण सफाईकर्मियों की मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन, राज्यसभा सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल से मिला प्रतिनिधिमंडल



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में उ.प्र. पंचायतीराज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने संघ की लंबित मांगों के निराकरण को लेकर राज्यसभा सदस्य एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल से शिष्टाचार भेंट कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। संघ के पदाधिकारियों ने ग्रामीण सफाईकर्मियों की समस्याओं एवं लंबे समय से लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए विभागीय सेवा नियमावली बनाए जाने तथा ग्रामीण सफाईकर्मियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाने की मांग रखी। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने मांग

पत्र पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई कराने का पूर्ण आश्वासन दिया। संघ ने सदस्य द्वारा दिए गए आश्वासन पर उनका आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि ग्रामीण सफाईकर्मियों की वर्षों पुरानी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा। इस अवसर पर संघ के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष कुलदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष बसंतलाल, महामंत्री मयंक वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकिशन, लखनऊ मंडल अध्यक्ष पवन कुमार वाल्मीकि तथा प्रदेश संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण सफाईकर्मियों लंबे समय से अपने अधिकारों एवं सेवा संबंधी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं और सरकार से उनकी मांगों के शीघ्र समाधान की अपेक्षा रखते हैं।

# लखनऊ नगर निगम का अतिक्रमण पर शिकंजा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने, अवैध अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के लिए नगर निगम ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान गंदगी फैलाने वालों, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों और सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीमों ने जोन-2 और जोन-5 क्षेत्रों में अभियान चलाकर नालियों की सफाई, कूड़ा उठान, सड़क सफाई और एंटी लावा छिड़काव कराया। साथ ही अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालान काटकर शमन शुल्क भी वसूला



गया। जोन-2 क्षेत्र में जोनल अधिकारी मनोज कुमार यादव, जोनल सेनेटरी गार्ड इस विशेष अभियान के दौरान गंदगी फैलाने वालों, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों और सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीमों ने जोन-2 और जोन-5 क्षेत्रों में अभियान चलाकर नालियों की सफाई, कूड़ा उठान, सड़क सफाई, कूड़ा उठान और एंटी लावा छिड़काव कराया गया। इस दौरान नालियों की सफाई, सड़क सफाई, कूड़ा उठान और एंटी लावा दवा का छिड़काव कराया गया। नगर निगम के 296 प्रवर्तन दल ने बुलाकी अड्डे से

पत्थर कट्टा मस्जिद और मोहन रोड तक अभियान चलाकर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ दो चालान कर 8 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला। वहीं प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर तीन चालान करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह जोन-2 में कुल 18 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। जोन-5 क्षेत्र में अवध चौराहे से हरदोई रोड स्थित कनौसी पुल तक और आलमबाग चौराहे से तालकटोरा रोड होते हुए लंगड़ा फाटक तक सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने 10 ठेलें, 3 गुमटियां और 5 कांटर हटाए। इसके अलावा तीन ठेलों को जल्द भी किया गया। अतिक्रमणकारियों को दोबारा सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर

कब्जा न करने की चेतावनी दी गई। अभियान के दौरान गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग के मामले में 3 हजार रुपये का शमन शुल्क भी वसूला गया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था, यातायात सुगमता और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं और प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें। जोन-5 में हुई कार्रवाई जोनल अधिकारी विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में कर अधीक्षक, जोनल सेनेटरी अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, प्रवर्तन दल और पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई।

# दहेज की मांग बनी मौत की वजह!

## शादी के चार माह बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी, पति-ससुर गिर तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज, लखनऊ। दहेज की मांग ने एक नवविवाहिता की जिंदगी लील ली। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के हुलासखेड़ा गांव में शादी के महज चार महीने बाद एक विवाहिता ने कथित दहेज उत्पीड़न से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि नामजद सास की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस के अनुसार बिजनौर थाना क्षेत्र के परवर परिचम निवासी मनोज ने तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री सीमा का विवाह 7 मार्च 2026 को हुलासखेड़ा निवासी अमित कुमार के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही पति अमित, ससुर रामचंद्र और सास ने कम दहेज मिलने का ताना देते हुए सीमा पर मायके से 72 लाख लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसके साथ मानसिक और



शारीरिक प्रताड़ना की जाती थी। परिजनों के मुताबिक करीब 15 दिन पहले सीमा रोते-बिलखते मायके पहुंची थी और उसने ससुराल में हो रही प्रताड़ना की पूरी जानकारी दी थी। परिजनों ने उसे समझाकर वापस भेज दिया, लेकिन ससुराल में हालात

नहीं बदले। 25 जुलाई को सीमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही मायके पक्ष मौके पर पहुंचा और दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। शिकायत के आधार पर मोहनलालगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)

की संबंधित धाराओं तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को दहेज को लेकर लगातार हो रहे विवाद और प्रताड़ना के साक्ष्य मिले। पुलिस का कहना है कि दहेज उत्पीड़न से मानसिक रूप से परेशान होकर सीमा ने आत्मघाती कदम उठाया। मंगलवार को पुलिस टीम में मेडईखेड़ा मोड़ के पास से आरोपी पति अमित कुमार और ससुर रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वहीं, नामजद सास की गिरफ्तारी के लिए प्रभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। मोहनलालगंज के सहायक पुलिस आयुक्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में पुलिस पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही है। दहेज उत्पीड़न के इस मामले में दो किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करने पड़ती है। दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। शिकायत के आधार पर मोहनलालगंज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)

# महमूदाबाद स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की बहाली की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद, सीतापुर। महमूदाबाद रेलवे स्टेशन पर पूर्व में संचालित ट्रेनों के ठहराव को पुनः प्रारंभ कराने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता व वरिष्ठ पत्रकार सुगमता और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं और प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें। जोन-5 में हुई कार्रवाई जोनल अधिकारी विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में कर अधीक्षक, जोनल सेनेटरी अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, प्रवर्तन दल और पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई।

को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि महमूदाबाद स्थित माँ संकटा देवी मंदिर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां सावन, नवरात्रि एवं अन्य पर्वों पर हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ट्रेनों का ठहराव बंद होने से यात्रियों को सीतापुर उतरकर लगभग 60 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करने पड़ती है। इसके अलावा महमूदाबाद में कई डिग्री कॉलेज एवं इंटर कॉलेज संचालित हैं। लखनऊ, सीतापुर, बुढ़वल और बालामऊ आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों को प्रतिदिन स्टेशन पर ट्रेन संख्या 54323/54324 बालामऊ-बुढ़वल पैसेंजर तथा 15211/15212 दरभंगा-अमृतसर जननायक एक्सप्रेस का ठहराव होता था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। इससे क्षेत्र के लोगों







## पुलिस ने वारंटी को किया गिरफ्तार

यल हो गया। बताया जा रहा है कि सड़क वह सड़क पर गिर पड़ा और उसे गंभीर अनुसार, शंभुदयाल वर्मा (55) पुत्र त्रयोदशी कार्यक्रम के लिए कोच मंडी रजिस्ट्रार कारनाक एक कुत्ता सड़क पर उसकी बाइक ह सड़क पर गिर पड़े।











